भारत - दक्षिण सूडान संबंध

दक्षिण सूडान 1899 से 1955 तक संयुक्त ब्रिटिश - मिस्र शासन के अधीन एंग्लो - मिस्र सूडान का हिस्सा था। दो गृह युद्ध (1962-72 एवं 1983-2005) के बाद, 09 जनवरी 2005 को नैरोबी, केन्या में सूडान सरकार तथा सूडान पीपुल्स लिबरेशन मूवमेंट (एप पी एल एम) के बीच एक व्यापक शांति करार (सी पी ए) पर हस्ताक्षर किए गए जिसने सूडान की स्वायत्तता एवं 6 साल की अवधि में आजादी पर दक्षिण सूडान के नागरिकों के जनमत संग्रह का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद दक्षिण सूडान ने एक शांतिपूर्ण जनमत संग्रह, जिसमें दक्षिण सूडान के 98.5 प्रतिशत नागरिकों ने आजादी के पक्ष में मतदान किया था, के बाद 09 जुलाई 2011 को सूडान से आजादी प्राप्त की। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य और अफ्रीकी संघ का 54वां सदस्य है। दो गृह युद्धों के दौरान भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया था इसलिए कुछ अन्य देशों से भिन्न इसका अतीत से कोई संबंध नहीं है। 1980 और 1990 के दशको में कंपाला, नैरोबी और किनशासा में भारतीय मिशनों एवं एस पी एल एम के बीच कुछ छिटपुट अनौपचारिक संपर्क थे। जब 1983 में युद्ध भड़का था तब जुबा एवं अन्य प्रमुख शहरों में भारतीय समुदाय के केवल कुछ बहादुर सदस्य रूके थे, जबकि अधिकांश सदस्य उत्तर की ओर चले गए थे।

दक्षिण सूडान के लोगों के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं। दिसंबर 1975 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री फकरूद्दीन अली अहमद ने सूडान का दौरा किया था तथा जुबा में क्षेत्रीय जन सभा को संबोधित किया था। जुबा की लगभग पूरी आबादी उनकी अगवानी के लिए उमड़ पड़ी थी। खारतूम में दूतावास द्वारा एक आकलन में बताया गया : "कुल मिलाकर, जुबा की यात्रा से यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण सूडान के नागरिकों में भारत के लिए गहरा सम्मान है।" 2005 में द्वितीय गृह युद्ध की समाप्ति के बाद दक्षिण सूडान के साथ भारत ने अपनी भागीदारी में वृद्धि की। विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने 09 जनवरी 2005 को नैरोबी में सूडान सरकार तथा एस पी एल एम के बीच व्यापक शांति करार (सी पी ए), जिससे दक्षिण सूडान में शांति आई, पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया था। जुबा में भारतीय वाणिज्य दूतावास अक्टूबर 2007 में खोला गया जिसे आगे चलकर मार्च 2011 में दूतावास के रूप में स्तरोन्नत किया गया। भारत आजाद दक्षिण सूडान को मान्यता प्रदान करने वाले पहले देशों में शामिल था तथा भारत के माननीय उप राष्ट्रपति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने जुलाई 2011 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया था।

महत्वपूर्ण द्विपक्षीय यात्राएं

भारत की ओर से दिसंबर 1975 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री फकरूद्दीन अली अहमद ने जुबा (जो उस समय सूडान का हिस्सा था) का दौरा किया था। विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने जनवरी 2005 में नैरोबी में सूडान सरकार तथा एस पी एल एम के बीच व्यापक शांति करार (सी पी ए) पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया था। इसके बाद उनके नेतृत्व में जून 2011 में एक

बहुविषयक शिष्टमंडल ने दक्षिण सूडान का दौरा किया। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने 09 जुलाई 2011 को जुबा में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू एन जी ए) के दौरान अतिरिक्त समय में 24 सितंबर 2011 को न्यूयार्क में राष्ट्रपति सल्वा कीर मयारडिट से मुलाकात की। सूडान एवं दक्षिण सूडान में भारत के विशेष दूत ने द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान नियमित रूप से दोनों देशों का दौरा किया। संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक लेखा परीक्षा टीम ने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान मिशन (यू एन एम आई एस एस) की लेखा परीक्षा करने के लिए 11 अगस्त से 5 सितंबर 2014 के दौरान दक्षिण सूडान का दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री (वी के एस) जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लेने के लिए दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और विदेश मंत्री डा. बरनाबा मरियल बेंजामिन को निमंत्रण देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 12 और 13 जुलाई 2015 को जुबा, दक्षिण सूडान का दौरा किया।

दक्षिण सूडान की ओर से डा. प्रिस्किला जोसेफ कुच के नेतृत्व में राष्ट्रपति सल्वा कीर के कार्यालय से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने अप्रैल 2011 में भारत का दौरा किया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री जोसेफ लुआल अचुइल ने नवंबर 2011 में भारत का दौरा किया। जनवरी 2012 में पंचगनी में फ्रेंड्स ऑफ मॉरल रिआर्मामेंट द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्व उप राष्ट्रपति डा. रीक मचार टेनी ने भारत का दौरा किया। कृषि, वानिकी एवं सहकारिता मंत्री श्री बेट्टी अचैन ओगवारो ने जनवरी 2012 में भारत का दौरा किया। दक्षिण सूडान के उप वाणिज्य मंत्री श्री केन्गेन जाकोर बेयो के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय शिष्टमंडल ने इंडो - अफ्रीकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के निमंत्रण पर जनवरी 2012 में मुंबई में आयोजित इलेक्रामा प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। नेशनल असेंबली के कान्स्टिचुवेंसी फंड कमेटी के अध्यक्ष बीट्रिस अबेर सैमसन ने जुलाई 2012 में भारतीय संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित भारत अध्ययन दौरे पर 8 सदस्यीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति जनरल साल्वा कीर मयारडिट अगस्त 2013 में भारत के दौरे पर आने वाले थे परंतु देश में खराब राजनीतिक स्थिति के कारण आखिरी क्षण में यात्रा स्थगित कर दी गई। एक उच्च स्तरीय आधिकारिक शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति साल्वा कीर ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में भाग लिया तथा शिखर बैठक के दौरान अतिरिक्त समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डा. बेरनाबा मरियल बेंजामिन ने भी शिखर बैठक के दौरान मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लिया तथा विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के साथ बातचीत की। दक्षिण सूडान के शिष्टमंडल में स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री तथा पेट्रोलियम मंत्री एवं अनेक विभिन्न सरकारी अधिकारी शामिल थे। दक्षिण सूडान के पेट्रोलियम मंत्री श्री स्टीफन धियू डाऊ तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने 21 एवं 22 जनवरी 2016 को नई दिल्ली में चौथे भारत - अफ्रीका हाइड्रो कार्बन सम्मेलन में भी भाग लिया।

आर्थिक - वाणिज्यिक संबंध

भारत के ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) ने 2003 से हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में दक्षिण सूडान एवं सूडान में लगभग 2.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है। चीन के सी एन पी सी, मलेशिया के पेट्रोनैस और सूडान के सुडापेस्ट के साथ कंसोर्टियम में ग्रेटर नील तेल परियोजना (जी एन ओ पी) (ब्लॉक 1, 2 और 4) में इसका 25 प्रतिशत प्रतिभागी हित (पी आई) है। पेट्रोनैस और सुडापेस्ट के साथ कंसोर्टियम में ब्लॉक 5 में इसका 24.125 प्रतिशत पी आई है।

भारत का दक्षिण सूडान के साथ व्यापार बहुत कम है। दक्षिण सूडान से भारतीय आयात की प्रमुख वस्तुओं में तेल एवं टिम्बर शामिल हैं तथा भारत के निर्यात में मुख्य रूप से उपभोक्ता एवं घरेलू वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, भेषज पदार्थ, टू एंड थ्री ह्वीलर मोटरसाइकिल शामिल हैं। चूंकि भारत का व्यापार मुख्य रूप से तीसरे देशों (केन्या, संयुक्त अरब अमीरात) के माध्यम से होता है, इसलिए सटीक डाटा उपलब्ध नहीं है। 2013 में दक्षिण सूडान का अनुमानित वैश्विक आयात 1.8 बिलियन अमरीकी डालर था तथा निर्यात लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें यूगांडा एवं केन्या प्रमुख व्यापार साझेदार थे। दक्षिण सूडान ने 2014 में तेल के निर्यात के माध्यम से 3.376 बिलियन अमरीकी डालर अर्जित किया था। तिलोनिया, राजस्थान में बेयरफुट कॉलेज (समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र) और एवांगेलिकल प्रेबीस्टेरियन चर्च (दक्षिण सूडान सरकार की ओर से) ने येई के गांवों में सौर विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक्वाटोरिया राज्य, दक्षिण सूडान के येई प्रांत में एक क्षेत्रीय बेयरफुट प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक केंद्र (आर बी टी वी सी) स्थापित करने के लिए 18 अगस्त को एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय ने भी दक्षिण सूडान में आर बी टी वी सी स्थापित करने के लिए 500,000.00 अमरीकी डालर (2.48 करोड़ रुपए) तक की निधि प्रदान के लिए बेयरफुट कॉलेज के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।

कुछ भारतीय कंपनियां निर्माण, बोरहोल ड्रिलिंग, मुद्रण, ट्रेडिंग एवं तेल उद्योग को सेवा जैसे क्षेत्रों में प्रचालन कर रही हैं। भारतीय जुबा में होटल एवं सुपर मार्केट का भी संचालन करते हैं। इंडिया - अफ्रीका चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में एक विशाल भारतीय कारोबारी शिष्टमंडल ने एक अन्वेषण मिशन पर अप्रैल 2013 में जुबा का दौरा किया तथा संयुक्त उद्यम एवं साझेदारी के लिए दक्षिण सूडान के कारोबारियों के साथ सार्थक बातचीत की।

विकास सहायता साझेदारी

अप्रैल 2005 में ओस्लो दाता सम्मेलन में भारत ने सूडान में अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं जैसे कि अस्पताल एवं शैक्षिक संस्थाओं के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की घोषणा की। सूडान के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान का आधा दक्षिण सूडान में एक अस्पताल के निर्माण के लिए आबंटित किया गया है।

जुबा में एक मध्यम आकार के अस्पताल के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है तथा उम्मीद है कि इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए दक्षिण सूडान सरकार और भारत सरकार के बीच एम ओ यू को शीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जनवरी 2008 में भारत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 100,000 अमरीकी डालर मूल्य के तंबुओं एवं दवाओं को दान में दिया था जिसे सूडान एवं दक्षिण सूडान के बीच साझा किया जाना था।

विकास सहायता की अन्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) आई सी सी आर छात्रवृत्तियां : भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) ने शैक्षिक वर्ष 2016-17 के लिए भारत में उच्च अध्ययन के लिए दक्षिण सूडान के नागरिकों के लिए सात (7) छात्रवृत्तियां आबंटित की है तथा सभी छात्रवृत्तियों का उपयोग कर लिया गया है।
(ii) भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम 2014-15 के दौरान विदेश मंत्रालय ने आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत दक्षिण सूडान के लिए 80 स्लॉटों का आबंटन किया था। वर्ष 2015-16 के लिए भारत के विदेश मंत्रालय ने आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत दक्षिण सूडान के लिए 60 स्लॉटों का आबंटन किया था।
(iii) व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वी टी सी) : वी टी सी भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक (आई ए एफ एस) की प्रतिबद्धता है। दक्षिण सूडान सरकार ने पश्चिमी बहर अल घजाल राज्य में वाऊ काउंटी में वी टी सी स्थापित करने का प्रसताव किया था तथा मामला दक्षिण सूडान सरकार के साथ विचाराधीन है।
(iv) सौर विद्युतीकरण : जुबा के निकट भारत के सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित सौर विद्युतीकरण परियोजना की काफी प्रशंसा की जा रही है; और
(v) अस्पताल का निर्माण : जुबा में अस्पताल के निर्माण के लिए दक्षिण सूडान को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है तथा जुबा में अस्पताल का निर्माण शुरू करने के लिए एम ओ यू पर हस्ताक्षर शीघ्र किए जाएंगे।
(vi) अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क परियोजना : दक्षिण सूडान में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए करार पर हस्ताक्षर फरवरी 2012 में किए गए थे। प्रस्ताव कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है।

दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सैन्य दल (यू एन एम आई एस एस)

यू एन एम आई एस एस में भारत की लगभग 2000 कार्मिकों की दो बटालियन हैं जो दक्षिण सूडान के दो सबसे बड़े राज्यों - जोंगलेई और अपर नील में तैनात हैं। इसके अलावा, लगभग 37 भारतीय पुलिस अधिकारियों का एक पुलिस कंपोनेंट है जो पुलिस संरचना के निर्माण में दक्षिण सूडान राष्ट्रीय पुलिस सेवा की मदद कर रहे हैं तथा अनेक असैन्य अधिकारी यू एन एम आई एस एस के विभिन्न अन्य विभागों में हैं। भारतीय सेना के सैन्य दल समाज कल्याण के अनेक कार्य कर रहे हैं जैसे कि चिकित्सा शिविर लगाना, शैक्षिक संस्थाओं को पुस्तकें डोनेट करना,

सड़कों का निर्माण करना आदि, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा काफी प्रशंसा की जा रही है। 09 अप्रैल 2013 को जोंगलेई राज्य में यू एन रक्षा दल को पिबोर से बोर ले जाते समय 36 भारतीय सैनिकों पर विद्रोहियों ने भीषण हमला बोल दिया। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी तथा 4 सैनिक मारे गए और 4 भारतीय सैनिक घायल हो गए। 19 दिसंबर 2013 को अकोबो (जोंगलेई राज्य) में यू एन बेस पर एक हमले में भी 2 भारतीय सैनिक मारे गए थे। अप्रैल 2014 में जोंगलेई राज्य में यू एन बेस पर एक हमले के दौरान 2 भारतीय सैनिक घायल भी हो गए थे।

दक्षिण सूडान में भारतीय समुदाय

दक्षिण सूडान में इस समय भारतीय नागरिकों की संख्या 700 के आसपास है। उनमें से कुछ ने जुबा में व्यवसाय स्थापित किया था तथा अन्य विभिन्न कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी संख्या में भारतीय नागरिक दक्षिण सूडान में क्रिश्चियन मिशनरी के संगठनों में भी काम करते हैं। इसके अलावा, यू एन एम आई एस एस में भारतीय सेना के 2000 शांति रक्षक, 37 पुलिस अधिकारी तथा कुछ असैन्य अधिकारी भी हैं। भारतीय 2006 के पूर्वार्ध में जुबा में होटल, बोरहोल कंपनियां, प्रिंटिंग प्रेस एवं विभागीय स्टोर खोलने वाले पहले लोगों में शामिल हैं। जुबा में भारतीय नागरिकों ने एक भारतीय संघ का निर्माण किया है, जिसकी सदस्यता इस समय 300 के आसपास है। दूतावास दक्षिण सूडान में भारतीय समुदाय के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है तथा उनकी विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं को सुगम बनाता है। दक्षिण सूडान के स्थानीय समुदाय के लिए स्थानीय अस्पताल के सहयोग से जून 2015 में भारतीय डाक्टरों द्वारा जुबा में एक दो दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जुबा, दक्षिण सूडान में 21 जून 2015 को भारतीय संघ के साथ मिलकर मिशन द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। भारतीय समुदाय के सदस्यों की समस्याओं को दूर करने के लिए हाल ही में एक खुले सत्र का आयोजन किया गया। मिशन ने पहली बार जुबा में 09 जनवरी 2016 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया तथा दक्षिण सूडान में डायसपोरा के हितों को बढ़ावा देने के लिए डायसपोरा के 9 प्रख्यात सदस्यों को सुगमता प्रदान की।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, जुबा की वेबसाइट :
http://indembjuba.org/

*****

जनवरी, 2016